

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक :- एफ.3(1)(5) रोल/निर्वा./2004/मानदेय/58।

जयपुर, दिनांक : 4/2/16

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर), राजस्थान ।

विषय:- मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण (NERPAP) हेतु राष्ट्रीय अभियान - बी.एल.ओ. एवं सुपरवाइजर्स को एकमुश्त मानदेय भुगतान के संबंध में।

प्रसंग- इस विभाग का समसंख्यक आदेश क्रमांक 1375 दिनांक 13.04.2015 एवं पत्र क्रमांक एफ. 3(2)(1) रोल/निर्वा./2015/NERPAP/4170 दिनांक 29.10.2015 तथा आयोग के पत्र क्रमांक 23/BLO /2015-ERS दिनांक 29.01.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1375 दिनांक 13.04.2015 के द्वारा मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण अभियान के दौरान मतदाता सूचियों में पंजीकृत मतदाताओं के डेटाबेस को आधार कार्ड नम्बर से लिंक करने तथा मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण के विषय में विभिन्न कार्य करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी/पर्यवेक्षकों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार क्रमशः 2500/- एवं 5,000/- रुपये मानदेय स्वीकृत किया गया था।

इस विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक एफ. 3(2)(1) रोल/निर्वा./2015/NERPAP/4170 दिनांक 29.10.2015 का अवलोकन करें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) नम्बर 494/2012 में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 11 अगस्त, 2015 के क्रम में उक्त अभियान बीच में ही रोक दिया गया था इसलिए बूथ लेवल अधिकारी/पर्यवेक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय के भुगतान करने के विषय में भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु प्रकरण आयोग को प्रेषित किया गया था।

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 29.01.2016 से यह निर्देश दिये हैं कि चूंकि मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण का कार्यक्रम बीच में ही स्थगित कर दिया गया था इसलिए बी.एल.ओ./पर्यवेक्षकों को दिये जाने वाले एकमुश्त मानदेय की स्वीकृत राशि में से वर्तमान में 50 प्रतिशत राशि का ही भुगतान किया जाए, शेष राशि का भुगतान मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन की प्रकिया के दौरान आयोग द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर किया जाएगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आयोग के संलग्न पत्र दिनांक 29.01.2016 में दिये गये निर्देशानुसार जिन बूथ लेवल अधिकारियों/पर्यवेक्षकों ने इस राष्ट्रीय अभियान के दौरान सेवाएं दी गयी है उन्हें आयोग द्वारा स्वीकृत राशि यथा 2500/- एवं 5,000/- में से वर्तमान में 50 प्रतिशत राशि का ही भुगतान किया जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त भुगतान इस वित्तीय वर्ष में ही किया जाना सुनिश्चित करें। जिन जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा बी.एल.ओ./पर्यवेक्षकों को इस अभियान से संबंधित मानदेय का भुगतान कर दिया गया है तो भुगतान की गयी अधिक राशि का समायोजन बूथ लेवल अधिकारियों/पर्यवेक्षकों को दिए जाने वाले वार्षिक मानदेय से किया जावे।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीया,

—E—

(राजेश यादव)

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ.3(1)(5) रोल/निर्वा./2004/मानदेय/58)

जयपुर, दिनांक : 4/2/16

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

E-mail/Speed Post

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 23/BLO/2015-ERS

Dated: 29th January, 2016

To,

The Chief Electoral Officers
of all States/UTs.

Addy CEO

2-2-16

Subject: Improvement in Electoral Roll-National Electoral Rolls Purification and Authentication Programme- release of one time remuneration to BLOs and Supervisors-regarding.

Sir,

I am directed to refer to the Commission's instructions vide its letter No. 23/1/2015-ERS (NERPAP), dated 16th March 2015 on the subject cited (a copy enclosed for ready reference) which provides for a one time remuneration of Rs. 2500/- for a BLO and Rs. 5000/- for a Supervisor for supervision in 8-10 polling stations for NERPAP in addition to his/her normal annual honorarium/remuneration and to state that proposals have been received from some Chief Electoral Officers for payment of above-said one time remuneration to the BLOs/Supervisors on prorata basis.

The Commission has considered the above-said proposals and has decided to allow release of 50% of prescribed one time remuneration mentioned above to the BLOs/Supervisors, who were engaged in NERPAP activities in all States/UTs. The remaining 50% of the remuneration in question shall be released after ongoing continuous updating of electoral rolls for which separate instructions would be issued by the Commission at appropriate time.

Accordingly, you may release 50% of the prescribed one time remuneration to the BLOs/Supervisors who were engaged in NERPAP activities in your State immediately.

This disposes of letters Nos. F.3(1) (5) /Roll/Nirva/2004/142, dated 11th January 2016 and IE (A)-8/2015/8582/Elec., dated 30th September 2015 of CEOs of Rajasthan and Odisha respectively.

Yours faithfully,

(NARENDRA N. BUTOLIA)
SECRETARY

437
Date... 29.1.16
3/2
DY-CEO

By E-mail / Speed post

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

Date: 16th March, 2015

No. 23/1/2015-ERS (NERPAP)

To,

The Chief Secretaries of
all States / UTs

Subject: - Improvement in Electoral Roll – Launching of National Electoral Rolls Purification and Authentication Programme (NERPAP) – reg.

Sir/Madam,

I am directed to inform that as you are aware the Commission, with the objective of bringing a totally error free and authenticated electoral roll, has launched a comprehensive programme, i.e., National Electoral Rolls Purification and Authentication Programme (NERPAP) w.e.f. 03.03.2015, with a clear timeline for completion by 15.08.2015. A copy of Commission's instructions contained in letter No. 23/1/2015 - ERS dated 27.02.2015 is enclosed herewith for information.

2. The Commission has reviewed preparedness of programme with Chief Electoral Officers of all States and UTs through a Video Conference on 12.03.2015. Several Chief Electoral Officers have informed that the Electoral Registration Officers in many States have not been provided regular manpower as data entry operators and IT infrastructure at their offices, required for this programme.

3. The Commission has considered the requests from the Chief Electoral Officers and has desired that the offices of EROs / AEROs may kindly be strengthened immediately and every ERO / AERO should be provided with atleast one computer with internet connection and one printer along with one data entry operator in his office exclusively for election work.

4. The Commission has also directed that the vacancies of Booth Level Officers, if any, may be filled immediately so that the ground work for the programme can be completed within the given schedule. In this connection, the Commission has approved a one time remuneration of Rs. 2500/- for a BLO and Rs. 5000/- for a Supervisor for supervision in 8 - 10 polling stations for this programme. The remuneration of Rs. 2500/- as mentioned, to the BLOs will be in addition to the annual honorarium / remuneration, currently being paid to them.

5. The Commission has asked the Chief Electoral Officers to make specific proposals on the above points to the State Government. It is requested that the proposals whenever received from Chief Electoral Officers may kindly be considered positively.

Yours faithfully,


(NARENDER N BUTOLIA)
SECRETARY

Copy to :- ✓ Chief Electoral Officers of all States / UTs. They are requested to send specific proposals as regards infrastructure in ERO's offices and remuneration to BLOs and Supervisors to the Chief Secretary immediately with a copy of the same to the Commission.